

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017

विषय:- लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रधान मंत्री पुरस्कार, 2018 के संबंध में।

प्रसंग:- कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-के-11011/01/2017-ए आर-। (5295) दिनांक 09.08.2017, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-11247 दिनांक 31.08.2017 तथा इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-12/(139)/2017-डी पी डी दिनांक 26.09.2017, श्री जितेन्द्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-के-11011/01/2017-ए आर(5359) दिनांक 14.09.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-के-11011/01/2017-ए आर-। (5295) दिनांक 09.08.2017 के आलोक में दिनांक 21.04.2018 को नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस, 2018 के आयोजन के समय लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु वितरित होने वाले प्रधान मंत्री पुरस्कारों के अवसर पर राज्य की भागीदारी विधिवत् सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध विभागीय पत्रांक-11247 दिनांक 31.08.2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पूर्व में किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि श्री जितेन्द्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-के-11011/01/2017-ए आर(5359) दिनांक 14.09.2017 तथा सचिव, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-12/(139)/2017-डी पी डी दिनांक 26.09.2017 के पत्र भी विषयगत संदर्भ में प्राप्त हुए हैं-सुलभ प्रसंगवश इन पत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न हैं। प्रासंगिक पत्रों में सिविल सेवा दिवस, 2018 के अवसर पर वितरित होने वाले प्रधान मंत्री पुरस्कारों के लिए चिह्नित प्राथमिकता आधारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन

को राज्य में गति प्रदान करने की अपेक्षा के साथ प्रधान मंत्री पुरस्कारों की प्रतियोगिता में जिलों की भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध है।

3. अतः अनुरोध है कि संलग्न पत्रों के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई ससमय सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक

सिद्धेश्वर चौधरी,
भारत सरकार के टावर सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमुखीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक: 21 अगस्त, 2017

विषय:- लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2018 के संबंध में ।
प्रसंग:- कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-के-11011/01/2017-ए आर-1 (5295) दिनांक-09.08.2017.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की अनुलग्नक सहित छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के विशिष्ट और नवाचारी कार्यों को मान्यता देने, पहचान दिलाने और पुरस्कृत करने के निमित्त भारत सरकार द्वारा लोक प्रशासन के उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार स्थापित किया गया है। ये पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सिविल सेवा दिवस के अवसर पर दिये जाते हैं।

2. आलोच्य पुरस्कार भारत सरकार के प्राथमिकता आधारित कार्यक्रमों को उत्कृष्टता से लागू करने के लिए दिये जाते हैं।

साथ ही, पर्यावरण संरक्षण, आयदा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और शिशु केन्द्रित नवाचार आदि भी इस संदर्भ में विचारित होंगे।

3. सिविल सेवा दिवस -2018 के अवसर पर प्रदान किये जाने वाले प्रासंगिक पुरस्कारों के लिये चिह्नित प्राथमिकता आधारित कार्यक्रम अग्रलिखित हैं :-

- (i) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
- (ii) प्रोमोटिंग डिजिटल प्रेमेंट्स।
- (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण एवं शहरी)।
- (iv) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना(डी डी यू जी के बाई)।

4. प्राथमिकता आधारित कार्यक्रमों से संबंधित पुरस्कारों के लिए जिला द्वारा भारत सरकार के स्तर से अधिसूचित होने वाले प्रपत्र में समर्पित किये जा सकते हैं। नवाचारों के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के संगठन (जिला सहित) आवेदन भेज सकते हैं। पुरस्कार हेतु विचारणीय अवधि अप्रैल, 2016 से दिसम्बर, 2017 है।

5. प्राथमिकता आधारित कार्यक्रम/कार्यक्रमों के पुरस्कारों की स्पर्धा में भाग लेने के लिए जिला द्वारा कम-से-कम एक कार्यक्रम का चयन अपेक्षित है। यद्यपि, जिलों द्वारा आधिकाधिक कार्यक्रमों का चयन किया जाना चाहिए ताकि उनकी व्यापक भागीदारी संभव हो सके।

6. साथ ही, केन्द्र/राज्य सरकारों के संगठनों/जिलों द्वारा पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और शिशु केंद्रित नवाचारों के लिए किये गये नवाचारी कार्यों को भी पुरस्कारों की स्पर्धा में रखा जा सकता है।

7. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा लोक प्रशासन के उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार के निमित्त एक पोर्टल विकसित किया गया है। यह उक्त विभाग की वेबसाइट (www.darpg.gov.in) पर उपलब्ध है। दिनांक-10.09.2017 तक प्राथमिकता आधारित कार्यक्रमों का ऑन- लाईन चयन करते हुए प्रत्येक जिला को उक्त पोर्टल पर निबंधन करा लेना है।

8. अतः अनुरोध है कि भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र के आलोक में अपेक्षित कार्यवाई ससमय सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाई की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:-सथोक्त।

विश्वसभाजन,

सरकार के अवर सचिव।

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक : 1/ वि०-1014/2017-सा० प्र०-1247/पटना-15, दिनांक: 15 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :- सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001 को कृपया सूचनार्थ।

सरकार के अवर सचिव।

डा. जितेन्द्र सिंह

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय,

राज्य मंत्री प्रधान मंत्री कार्यालय,

कार्मिक, लोक शिवशायत तथा पेंशन मंत्रालय,

परमाणु उर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग,

भारत सरकार



सत्यमेव जयते

DR. JITENDRA SINGH

Minister of State (Independent Charge)

Ministry Development of North Eastern Region,

Minister of State, Prime Minister's Office,

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions,

Department of Atomic Energy & Department of Space,

Government of India

Jitendra Singh

कृ०

23/9/17 14 SEP 2017

Respected Shri Nitish Kumar ji,

Government of India have instituted the "Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration" to acknowledge and recognize extraordinary and innovative work done by Districts and Central/ State Government organizations. The Awards are presented by the Hon'ble Prime Minister on the occasion of Civil Services' Day on 21st April every year.

2. The following priority programmes have been identified for the Awards to be given on the next Civil Services' Day on 21.04.2018 -

- (i) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana;
- (ii) Promoting Digital Payments;
- (iii) Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban & Rural; and
- (iv) Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana.

3. In addition, two Awards will be given for innovation in the field of environment conservation, disaster management, water conservation, energy, education and health, women and child centric initiatives, etc. Organizations of Central/ State Governments, as well as districts are eligible for PM's Awards on Innovations.

4. Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) has developed a web portal for online registration of Districts for choosing priority programmes to compete for PM's Awards. The link (<http://nceg.gov.in/pmawards/public/login>) of the portal is available on DARPG website (www.darpg.gov.in).

5. Government is keen to encourage a healthy competition among Districts for the awards which would go a long way in ensuring better service delivery for the citizens and good governance in the country. It is expected that each District shall choose at least one programme from the identified priority programmes. However, they may choose as many as they can from amongst the identified priority programmes, so that there can be wider participation.

6. I shall be grateful if you could issue necessary directions to the authorities concerned to accelerate implementation of the programmes, and motivate Districts to fully participate in the competition for PM's Awards.

With best regards,

Yours sincerely,

(Dr. Jitendra Singh)

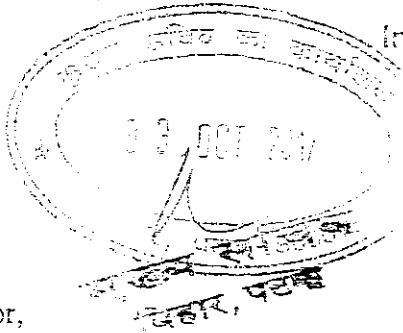
Shri Nitish Kumar
Hon'ble Chief Minister
Government of Bihar
Patna



भजय साहनी, आई.एस.एन.
AJAY SAWHNEY, I.A.S.

Handwritten notes:
GAD
11

सचिव
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
Secretary
Ministry of Electronics &
Information Technology (MeitY)
Government of India



O. No. 12(139)/2017-ITD
Dated: 26.09.2017

24/9/17 Dear Chief Secretary/Administrator,

Handwritten initials:
AS

Government of India has instituted 'Prime Minister Awards for Excellence in Public Administration' to acknowledge, recognize and reward extraordinary and innovative work done by officers of Central and State Governments. The awards are presented by the Hon'ble Prime Minister on the occasion of the Civil Services Day 2018.

Handwritten notes:
210-1
23/9/17
210/17

2. "Promoting Digital Payment" is one of programmes identified for Award this year. PM's Award will be given to the best performing district in the implementation of the Priority programme of Government of India.

3. All districts are eligible to apply for all priority programme. The period of consideration for the awards from 1st April 2016 to 31st December 2017. The process of registration has begun on the designated PM's award portal. The link for the same is available on the website of DARPG (www.darpg.gov.in). Each district is required to register on the portal to participate. The broad parameters identified for evaluation on promoting Digital Payment are enclosed herewith.

4. I request you to advise all the District Magistrates about the award, and ensure maximum participation from your state.

With regards,

Yours sincerely,

Handwritten signature and date:
AS
6/10

Handwritten signature:
(Ajay Sawhney)

Vertical stamp:
556
5/10/17

All Chief Secretaries/ Administrators-of the States/UTs.

Promotion of Digital Payments

Implementing Unit – District

Applicant - DCs/DMs

Period of Consideration- 1/4/2016 to 31/12/2017

Parameters for Evaluation:

- 1 Bank accounts seeded with Aadhaar and Mobile Numbers.
- 2 Digital payment facilities at Ration shops and Fertilizer shops.
- 3 The number of BHIM transactions per capita in a district and incentive delivered to the beneficiary for BHIM/BHIM Aadhaar schemes in the district.
- 4 Cash outflow per capita from banks in Sept-Oct 2017 as compared to that of Sept-Oct 2016.
- 5 Digital payment acceptance infrastructure with registered merchants in a district.
- 6 The number of Government established touch points accepting money through digital payments.
- 7 Increase in revenue collected from electricity bill payment through Digital modes in a district.
- 8 The number of PoS per capita in the district.
- 9 Registered merchants having Bharat QR code in the districts.
- 10 The number of Business Correspondence (BCs) with respect to rural population in a district.
- 11 Strategy/ Methodology adopted to promote Digital Payment in a district & Innovations adopted in implementation.
- 12 Transparency / accountability in the implementation